



|              |             |             |              |             |          |          |
|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|----------|----------|
| 14 मिनट      | 8           | 24          | 1            | GS1 • 7     | GS2 • 21 | GS3 • 16 |
| पढ़ने का समय | मुख्य खबरें | संक्षेप में | मेन्स प्रश्न | पेपर मिश्रण |          |          |

## 01 — आज 2 मिनट में

## 5 खबरें जो छोड़नी नहीं हैं

## 1 2027 की जनसंख्या जनगणना, स्वतंत्र भारत की पहली डिजिटल और जाति आधारित जनगणना

क्यों जरूरी: जनगणना 2027 महत्वपूर्ण है क्योंकि यह स्वतंत्र भारत में पहली डिजिटल और जाति-आधारित जनगणना होगी।

GS1 • भारतीय समाज

P

M

## 2 बिल से राज्यों की मिनरल टैक्स पावर खत्म, 11 प्रभावित क्षेत्र फिस्कल लिम्बो में

क्यों जरूरी: लोकसभा ने खनिज और खनिज पदार्थ (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 पारित किया है, जो खनिज अधिकारों पर कर लगाने की राज्यों की शक्ति को प्रतिबंधित करता है, जिससे संघीय राजकोषीय स्वायत्तता प्रभावित होती है।

GS3 • अर्थव्यवस्था

P

M

## 3 सुप्रीम कोर्ट का फैसला: भारत में हर गिरफ्तारी के लिए सीधा कम्युनिकेशन जरूरी

क्यों जरूरी: विहान कुमार बनाम हरियाणा राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने यह निर्णय दिया कि सत्ता के मनमाने प्रयोग को रोकने के लिए संबंधित व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों की प्रत्यक्ष सूचना देना अनिवार्य है।

GS2 • राजव्यवस्था एवं संविधान

P

M

## 4 यू.एस. रिपोर्ट में पुणे-गुजरात-चेन्नई बेल्ट को 'Great Transshipment Scam' में नामजद किया

क्यों जरूरी: व्हाइट हाउस ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें भारत के पुणे-गुजरात-चेन्नई बेल्ट को चीन द्वारा अमेरिकी टैरिफ से बचने के लिए अवैध पारगमन (transshipment) के एक केंद्र के रूप में नामित किया गया है।

GS2 • अंतर्राष्ट्रीय संबंध

P

M

## 5 बांग्लादेश के PM Tarique Rahman द्विपक्षीय talks के लिए भारत आएंगे

क्यों जरूरी: बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान, तनावपूर्ण संबंधों को पुनर्जीवित करने और रुकी हुई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को गति देने के उद्देश्य से द्विपक्षीय वार्ता हेतु भारत के दौरे पर जाने वाले हैं।

GS2 • अंतर्राष्ट्रीय संबंध

P

M

## GS1 · भारतीय समाज

P

M

## 2027 की जनसंख्या जनगणना, स्वतंत्र भारत की पहली डिजिटल और जाति आधारित जनगणना

**चर्चा में क्यों:** जनगणना 2027 महत्वपूर्ण है क्योंकि यह स्वतंत्र भारत में पहली डिजिटल और जाति-आधारित जनगणना होगी।

## याद रखें

- जनगणना 2027 स्वतंत्र भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी।
- Housing Listing Operations (HLO) का समापन 30 सितंबर, 2026 को हुआ।
- जनगणना के लिए स्व-गणना (Self-enumeration) 17 अगस्त से 31 अगस्त, 2026 तक उपलब्ध है।

**मेन्स कोण** भारत में सामाजिक-आर्थिक विकास की योजना बनाने में डिजिटल जनगणना गणना और जातिगत डेटा के समावेश के महत्व पर चर्चा कीजिए।

पूरा नोट → [satyadheesh.in/news/103890](https://satyadheesh.in/news/103890)

## GS3 · अर्थव्यवस्था

P

M

## बिल से राज्यों की मिनरल टैक्स पावर खत्म, 11 प्रभावित क्षेत्र फिस्कल लिम्बो में

**चर्चा में क्यों:** लोकसभा ने खनिज और खनिज पदार्थ (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 पारित किया है, जो खनिज अधिकारों पर कर लगाने की राज्यों की शक्ति को प्रतिबंधित करता है, जिससे संघीय राजकोषीय स्वायत्तता प्रभावित होती है।

## याद रखें

- खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026।
- यह विधेयक झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और मध्य प्रदेश सहित 11 राज्यों को प्रभावित करता है।
- यह विधेयक 2005 से संबंधित खनिज कर बकाया (mineral tax arrears) को शून्य कर देता है।

**मेन्स कोण** खनिज और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 के केंद्र और राज्यों के बीच राजकोषीय संघवाद तथा राजस्व-साझाकरण की गतिशीलता पर पढ़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण कीजिए।

पूरा नोट → [satyadheesh.in/news/103926](https://satyadheesh.in/news/103926)

## GS2 · राजव्यवस्था एवं संविधान

P

M

## सुप्रीम कोर्ट का फैसला: भारत में हर गिरफ्तारी के लिए सीधा कम्युनिकेशन जरूरी

**चर्चा में क्यों:** विहान कुमार बनाम हरियाणा राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने यह निर्णय दिया कि सत्ता के मनमाने प्रयोग को रोकने के लिए संबंधित व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों की प्रत्यक्ष सूचना देना अनिवार्य है।

## याद रखें

- अनुच्छेद 22(1) गिरफ्तारी के आधारों की जानकारी प्राप्त करने और कानूनी व्यवसायी से परामर्श करने के अधिकार की गारंटी देता है।
- Code of Criminal Procedure (CrPC) की धारा 50 व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों के बारे में सूचित करना अनिवार्य बनाती है।
- उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) भारत की सर्वोच्च न्यायिक संस्था है, जो कार्यकारी कार्यों पर न्यायिक पुनरावलोकन (judicial review) का प्रयोग करती है।

**मेन्स कोण** राज्य की मनमानी कार्रवाई के विरुद्ध मौलिक अधिकारों के संरक्षण को सुनिश्चित करने में गिरफ्तारी के दौरान प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों के महत्व का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

पूरा नोट → [satyadheesh.in/news/103786](https://satyadheesh.in/news/103786)

## GS2 · अंतर्राष्ट्रीय संबंध

P

M

## यू.एस. रिपोर्ट में पुणे-गुजरात-चेन्नई बेल्ट को 'Great Transshipment Scam' में नामजद किया

**चर्चा में क्यों:** व्हाइट हाउस ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें भारत के पुणे-गुजरात-चेन्नई बेल्ट को चीन द्वारा अमेरिकी टैरिफ से बचने के लिए अवैध पारगमन (transshipment) के एक केंद्र के रूप में नामित किया गया है।

## याद रखें

- अनिवार्य श्रम (forced labor) के आयात को रोकने में विफल रहने पर यू.एस. ने भारत पर 10% टैरिफ लगाया है।
- पुणे-गुजरात-चेन्नई बेल्ट को विशेष रूप से एक ट्रांसशिपमेंट हब (transshipment hub) के रूप में पहचाना गया था।
- यह रिपोर्ट अवैध ट्रांसशिपमेंट (transshipment) जोखिम से जुड़े 40 से अधिक देशों की पहचान करती है।

**मेन्स कोण** व्यापार संबंधी आरोपों और टैरिफ (शुल्क) अधिरोपण का भारत की 'मेक इन इंडिया' पहल और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ उसके द्विपक्षीय व्यापार संबंधों पर पढ़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण कीजिए।

पूरा नोट → [satyadheesh.in/news/103938](https://satyadheesh.in/news/103938)

## बांग्लादेश के PM Tarique Rahman द्विपक्षीय talks के लिए भारत आएंगे

**चर्चा में क्यों:** बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान, तनावपूर्ण संबंधों को पुनर्जीवित करने और रुकी हुई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को गति देने के उद्देश्य से द्विपक्षीय वार्ता हेतु भारत के दौरे पर जाने वाले हैं।

### याद रखें

- अगतला-अखौरा रेल-लिंक: यह उत्तर-पूर्वी भारत को बांग्लादेश से जोड़ता है।
- भारत ने 2009-2019 के बीच बांग्लादेश को \$8 बिलियन की Lines of Credit प्रदान कीं।
- दिनेश त्रिवेदी: बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त।

**मेन्स कोण** बांग्लादेश के साथ भारत की 'पड़ोस प्रथम' नीति को सुदृढ़ करने में बुनियादी ढांचा कनेक्टिविटी के महत्व पर चर्चा कीजिए।

पूरा नोट → [satyadheesh.in/news/104208](https://satyadheesh.in/news/104208)

## Turkey, Pakistan और Saudi Arabia ने NATO के Article 5 की तर्ज पर डिफेंस समझौता किया

**चर्चा में क्यों:** तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब ने एक पारस्परिक रक्षा समझौता किया है, जिसके तहत किसी एक सदस्य पर हमला सभी पर हमला माना जाएगा, जो NATO के अनुच्छेद 5 के समान है।

### याद रखें

- NATO Article 5: एक सामूहिक रक्षा खंड जो यह निर्धारित करता है कि एक सदस्य पर हमला सभी पर हमला है।
- नए समझौते के हस्ताक्षरकर्ता: Turkey, Pakistan और Saudi Arabia।
- यह समझौता तकनीकी और सैन्य प्रगति के लिए रक्षा उद्योग में सहयोग पर बल देता है।

**मेन्स कोण** पश्चिम एशिया और मध्य एशिया में उभरते त्रिपक्षीय रक्षा समझौतों के क्षेत्रीय सुरक्षा संरचना और भारत की 'पड़ोस पहले' (Neighborhood First) नीति पर पड़ने वाले निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।

पूरा नोट → [satyadheesh.in/news/104079](https://satyadheesh.in/news/104079)

## SEBI ने OBPPs को RBI, IRDAI, IFSCA और PFRDA द्वारा रेगुलेटेड प्रोडक्ट्स ऑफर करने की अनुमति दी

**चर्चा में क्यों:** SEBI ने पूंजी बाजार को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म (OBPPs) के दायरे का विस्तार किया है, ताकि वे विभिन्न वित्तीय निकायों द्वारा विनियमित उत्पादों की पेशकश कर सकें।

### याद रखें

- SEBI: Securities and Exchange Board of India, प्रतिभूति बाजार (securities market) को विनियमित करता है।
- IRDAI: Insurance Regulatory and Development Authority of India।
- IFSCA: International Financial Services Centres Authority।

**मेन्स कोण** ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म (OBPPs) के विस्तार से भारतीय ऋण बाजार में खुदरा भागीदारी को कैसे बढ़ावा मिल सकता है और इसमें निहित विनियामक चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।

पूरा नोट → [satyadheesh.in/news/104176](https://satyadheesh.in/news/104176)

## युवा बेरोजगारी बढ़कर 16.2% हुई, युवा महिलाओं के लिए नौकरी ढूँढना 20.7% मुश्किल

**चर्चा में क्यों:** आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) ने युवा बेरोजगारी में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की है, जो श्रम बाजार में बढ़ते लैंगिक और नगरीय-ग्रामीण अंतर को रेखांकित करता है।

### याद रखें

- जून 2026 में भारत में युवा बेरोजगारी दर 16.2% तक पहुंच गई।
- शहरी युवाओं में बेरोजगारी दर (18.2%) ग्रामीण युवाओं की बेरोजगारी दर (15.1%) से अधिक है।
- महिला युवा बेरोजगारी (20.7%) की दर, पुरुष युवा बेरोजगारी (14.6%) की तुलना में काफी अधिक है।

**मेन्स कोण** भारत में युवा बेरोजगारी में बढ़ते लैंगिक और शहरी-ग्रामीण अंतराल में योगदान देने वाले कारकों का विश्लेषण कीजिए और समावेशी रोजगार सृजन को बढ़ाने के लिए उचित उपाय सुझाइए।

पूरा नोट → [satyadheesh.in/news/104169](https://satyadheesh.in/news/104169)

## GS1 · इतिहास · समाज · भूगोल

भारत रजिस्ट्रार ने बर्फबारी वाले इलाकों में 1 सितंबर से शुरू होने वाली जनगणना के लिए 40 सवाल अधिसूचित किए

ज्ञान भारतम मिशन के तहत पांडुलिपियों के धीमे डिजिटाइजेशन पर संसदीय समिति ने जताई चिंता

मद्रास उच्च न्यायालय प्रशासन ने राष्ट्रीय गान से पूर्व 15 अगस्त, 2026 को 'वन्दे मातरम्' बजाने की घोषणा की है

अरुणाचल प्रदेश ने 80:20 आरक्षण खत्म किया, स्थानीय भाषा में दक्षता अनिवार्य

## GS2 · राजव्यवस्था · शासन · सामाजिक न्याय · अंतर्राष्ट्रीय संबंध

आज़ादी की पूर्व संध्या पर भारत ने "आतंकवाद को पनाह देने वाले" पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि निलंबित की

उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) द्वारा सांसद ए.ए. रहीम द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई की

करूर भगदड़ पीड़ितों के जॉब ऑर्डर पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, गांधी हेट स्पीच केस रद्द

कर्नाटक ने सार्वजनिक संपत्ति पर इवेंट्स के लिए परमिशन की मांग वाला बिल पेश किया

हरियाणा में electoral rolls का विशेष गहन पुनरीक्षण समस्या पैदा कर रहा है

केरल ने केयरगिवर सहायता ₹600 से बढ़ाकर ₹1,000 की की

पाकिस्तान भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा: Pew सर्वे में 54% लोगों ने पड़ोसी देश पर जताया अविश्वास

आंध्र मंत्री: राज्य की लगभग आधी आबादी ओवरवेट, जॉइंट टास्क फोर्स की योजना

2025 में भारतीयों पर विदेशों में हमले बढ़कर 104 हुए, ज्यादातर US, UAE, UK और Canada में

## GS3 · अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा

निवेशकों के लिए रेटिंग आसान बनाने हेतु Sebi ने 6 कलर कोड वाला Credit Risk-o-Meter प्रस्तावित किया

DRDO को 2026 तक AI में मुकाबला करने और सुव्यवस्थित होने के लिए PMO से मिले सुधारों पर काम करना होगा

मैग्नेटिक स्नैप्स ने कोरोना की 93% हीट को पावर देकर एनर्जी लॉस मिस्ट्री को खत्म किया

SEBI ने विदेशी क्लाइंट्स के लिए वीडियो-आधारित KYC का प्रस्ताव दिया, पब्लिक कमेंट्स मांगे

रक्षा मंत्रालय ने तोपखाने की सटीकता बढ़ाने और स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निजी फर्मों के साथ 'लॉइटर म्यूनिशन सिस्टम' (Loiter...

India ने MCX पर Crude Sunflower Oil futures contract लॉन्च किया

भारत के 80वें Independence Day पर रूसी कॉस्मोनेट्स Pyotr Dubrov, Anna Kikina

Lashkar-e-Taiba की धमकी के बाद कश्मीरी पंडित वर्कर्स को छुट्टी पर भेजा, पुलिस जांच में जुटी

पेलोड लॉन्च के लिए भारत खर्च कर रहा है \$13,302 प्रति Kg. प्रमुख स्पेस देशों में सबसे ज्यादा

जलवायु परिवर्तन नहीं, मानवीय गलतियों से असम में बाढ़, 103 की मौत

जर्मनी ने दुनिया के पहले लकड़ी के विंड टरबाइन ब्लेड लॉन्च किए, CO2 में 78% की कमी

GS1 • भारतीय समाज

भारत में सामाजिक-आर्थिक विकास की योजना बनाने में डिजिटल जनगणना गणना और जातिगत डेटा के समावेश के महत्व पर चर्चा कीजिए।



टेलीग्राम



वेबसाइट

हर सुबह **टेलीग्राम** पर पाएँ

रोज़ सुबह 5 बजे पीडीएफ + क्विज़ • हर रविवार साप्ताहिक • हिंदी और अंग्रेज़ी • मुफ्त, बिना साइन-अप।

[t.me/satyadheesh](https://t.me/satyadheesh) • [satyadheesh.in/upsc/reports](https://satyadheesh.in/upsc/reports)

नोट्स सत्याधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से बनाए जाते हैं और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़े हैं। उत्तर में उपयोग से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।